RAJYA SABHA

Tuesday, the 20th August, 1985/29 Sravana, 1907 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*381. [*The questioner (Prof. C. Lakshmanna) was absent. For answer* vide cols. 37—40 infra.]

Irregularities in the NTC

*382. SHRI K. VASUDEVA PANICKER†:

SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:

Will the Minister of SUPPLY AND TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are charges of gross irregularities, nepotism and outright graft against several top officials of the National Textile Corporation;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what are the details of the cases pending against them and the number of officials of the Corporation who have been convicted during the last three years; and

(d) what steps Government propose to take to revamp the Corporation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri K Vasudeva Panicker.

Statement

(a) to (c) There are 67 disciplinary proceedings being processed against officials of NTC and its subsidiaries.

These 67 cases pertain to the following categories of officers:—

(A) CMDs/Functional Directors of Subsidiary Companies .	5
(B) Other officers with pay scale of Rs. 1800 and above .	16
(C) Officers with pay scale below Rs. 1800 per month .	46
TOTAL .	67

The cases against the 21 senior officials as at (A) and (B) pertain to undue favour shown in sales, purchases; false TA DA mis-use of office car, mis-use of Leave Travel Concession, false insurance claim, disproportionate assets etc. 46 cases under the category (C) above relate to false TA/DA, Leave Travel Concession, false medical claims, favouritism in recruitment, pilferage, irregularities in purchases/sales etc.

No official of the NTC has been convicted by a Court of law during the last three years.

(c) Closer monitoring of the working of NTC and strengthening of the vigilance by Holding Company is being done besides improving the procedures to reduce the scope for malpractices.

SHRI K. VASUDEVA PANICKER: How many surprise checks were conducted by the Government in order to check the irregularities and corrupt practices in NTC and its subsidiary corporations?

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: I cannot just now give you the number of surprise checks that have been made but a number of steps have been taken to

strengthen the vigilance in the NTC. We have also taken positive action, concrete action against those who have been found guilty of some lapses.

SHRI K. VASUDEVA PANICKER: I would like to know whether the Government proposes to fill up the vacancies at the top level also due to resignations, dismissals, suspensions etc. of officials

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Just now there are two vacancies at the level of the CMD of the different subsidiaries and I hope we will be able to fill them up very quickly.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है उनके नाम को देने में क्या परेशानी है ? क्या यह सच है कि एन० टी० सी० द्वारा कार्रवाई शुरू किये जाने के बाद कुछ बड़े अधिकारी सेवा से निकाले गये ? जिन अधिकारियों को सेवा से निकाला गया उनके विरुद्ध और क्या कानूनी कार्रवाई की गयी और उसके क्या परिणाम निकले है और इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह भी सच है कि कार्रवाई के डर से कुछ बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है ? जिन अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है उनका इस्तीफा मंजूर करने से पहले उनके विरुद्ध क्या कानूनी अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की गई ? और अगर की गई तो उसके क्या परिणाम निकले ? मैं अनुभव करता हूं कि अनुशासनिक कार्रवाई से कुछ नहीं होगा । अच्छा होता कि सी० बी० आई० से जांच करवाई जाती ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अभी सी० एम० डी० के लेवल पर एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है लेकिन उनके विरुद्ध कुछ इस प्रकार के आरोप नहीं थे और दूसरे कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे को मंजूर किया गया । जहां तक सी० बी० आई० की इंक्वायरी की जरूरत है, मैं बताना चाहता हूं कि सी० बी० आई० की इंक्वायरी के लिये आग्रह किया गया है और उसके कागजात हमारे पास मौजूद हैं । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको उससे सूचित कर दूंगा । लेकिन पिछले दिनों एन० टी० सी० के अधिकारियों के खिलाफ काफी बड़ी कार्रवाई की गई है । जैसा मैंने कहा कि सीनियर आफिसर्स के लेवल पर 34 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे किये गये जिसमें 16 पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और बाकी के मामलों में कार्रवाई लम्बित है । कुल 67 मुकदमे किये गये ।

श्री चतुरानन मिश्र : श्रीमन, मेरी सूचना के मुताबिक यह जो कार्रवाई की जा रही है अनुशासनात्मक कार्रवाई वह एक-डेढ़ साल से ज्यादा दिनों से चल रही है । इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार का मामला है उसके निष्पादन के लिये क्या कोई सीमा निर्धारित है जिसके भीतर उसमें निर्णय लिया जा सके ? कोई टाइम लिमिट है ? अगर नहीं है तो उसमें सीमा निर्धारण करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सीमा कोई निर्धारित नहीं है । लेकिन हम लोगों की तरफ से यह प्रयास बराबर किया जाता है कि इसका निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र हो । कुछ अधिकारियों के मामलों को पहले भी हम लोगों ने रिव्यू किया है और किसी स्तर पर कोई विलम्ब है तो उसको ठीक करने की कोशिश की है । हमारे पास विस्तृत सूचना है, प्रत्येक मामले के बारे में सूचना है । लेकिन यहां समय नहीं है जिसमें सदन को हर मामले की सूचना दी जा सके ।

श्री चतुरानन मिश्र : आपने कोई निश्चित अवधि रखी है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सरकार निश्चित रूप से आपकी इस भावना के साथ है । सभी ऐसे मामलों में कार्यवाही कर रही है और आगे भी करेंगे जिससे इन मामलों का निष्पादन निश्चित अवधि के भीतर हो सके और जल्दी से जल्दी हो सके ।

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Sir, may I know from the Minister how many cases have been filed against

the officials and whether they have been acquitted? Why they are acquitted if they are not punished?

MR. CHAIRMAN: It is the court which acquits.

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: It is in the reply, Sir.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Sir, I have already stated that 34 cases against senior officers of the NTC have been launched in 1984-85. Out of these 34, action has been completed in 16 cases and inquiry is pending in 18 cases. In one case, the case was closed with the observation of the Central Vigilance Commissioner because a *prima facie* case was not found against him. The cases are closed only when there is a precise recommendation from the relevant authority that it cannot be proceeded further.

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Not one case is filed in the court.

MR. CHAIRMAN: No. Please don't answer.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे देश में सिक मिलें हैं उनमें एन० टी० सी० में कितनी सिक मिलें हैं ? अगर एन० टी० सी० में करप्ट आफिशियल्स की इररैगुलेरिटीज की वजह से कुछ मिलें सिक हुई हैं तो ऐसी सिक मिलों की संख्या कितनी है और ऐसे आफिशियल्स के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह: एन० टी० सी० में सिक मिलें हैं, यह स्थिति नहीं है । एन० टी० सी० तो सिक मिलों के लिये ही तैयार किया गया है और उसके अंदाज में यह कहना कठिन है कि कौनसी सिक मिल नहीं है । लेकिन आम तौर से एन० टी० सी० का परफोरमेंस पिछले दिनों में काफी अच्छा रहा है और यह एक ऐसा अस्पताल है जहां पर मिलें बीमार होकर आती हैं और वे स्वस्थ हो रही हैं ।

Representation of Workers at the Board of Directors' level in the public sector undertakings

*383. DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA:

SHRI V. GOPALSAMY:†

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of those public sector undertakings where workers are at presented at the Board of Directors' level;

(b) what are the names of those undertakings where workers have no representation at the Board of Director's level;

(c) what steps are being taken to give them representation at the Board level?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) A Scheme of Workers' Participation was notified by the Ministry of Labour on 30th December, 1983. The Scheme envisages participation of labour at the shop-floor and plant levels in all public sector undertakings except those which have been specifically exempted. As regards participation at the Board level, the scheme envisages that the administrative Ministry/ Department concerned will draw, in consultation with the Ministry of Labour a list of undertakings which it considers would be suitable for introduction of the Scheme at the Board level also. This information is being collected and will be laid on the Table of the House.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, the Public Undertakings Committee of Parliament in its Seventeenth Report (1971-72) recommended as follows: The Committee was strongly in favour of participation of workers and their representatives in management of public undertakings. By workers' participation in management the Commit-

†This question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Gopalsamy.